



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 758]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 सितम्बर 2025 — अश्विन 8, शक 1947

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29 सितम्बर 2025

अधिसूचना

क्र. GENCOR-35/2648/2025-C&I.— राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य में औद्योगिक विकास को अधिक गति प्रदान करने के लिए लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव, राज्य शासन, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका (12.29) एवं अध्याय (स-4) की कंडिका (12) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसरण में, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के माध्यम से राज्य में वृहद उद्योग की स्थापना हेतु, राज्य में “इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स” सेक्टर में निवेश हेतु, मेसर्स केजीवी हाइब्रिड ग्रीन मोबिलिटी प्रायवेट लिमिटेड के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज (बी-स्पोक पैकेज) का निर्धारण निम्नानुसार करता है:-

1. औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए “इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर” के लिए अध्याय (स-4) में प्रावधान किए गए हैं। मेसर्स केजीवी हाइब्रिड ग्रीन मोबिलिटी प्रायवेट लिमिटेड द्वारा राज्य में हाइब्रिड ग्रीन मोबिलिटी बाईक एवं किट विनिर्माण हेतु 1100 करोड़ रुपये निवेश एवं 200 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजित होना प्रस्तावित किया गया है।

2. इस पैकेज के अंतर्गत निम्नानुसार अनुदान/छूट/रियायत की मदवार स्वीकृति की जाती है:-

(1) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान - मान्य स्थायी पूंजी निवेश का 50%, 6 किस्तों में वितरित किया जाएगा।

(2) ई.टी.पी. अनुदान - ई.टी.पी. स्थापना लागत का 30% अधिकतम रु 50 लाख प्रदान किया जाएगा।

(3) रोजगार सृजन अनुदान - प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 3 वर्षों तक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी कर्मचारियों हेतु रु 8,000 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह, अधिकतम रु 30 लाख प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा।

(4) पर्यावरणीय प्रबंधन परियोजना अनुदान - कार्बन फुटप्रिन्ट कम करने वाली/ कार्बन क्रेडिट प्रदान करने वाली प्लांट एवं मशीनरी पर किए गए व्यय का 50%, अधिकतम रु 2.5 करोड़ प्रदान किया जाएगा।

(5) अध्याय स-4 में उल्लेखित अन्य निवेश प्रोत्साहन भी प्रदान किये जाएंगे।

3. यह पैकेज निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा-

(1) आर्थिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता - कंपनी को इस पैकेज का लाभ तभी मिलेगा, जब वह न्यूनतम रु. 1000 करोड़ का स्थायी पूंजी निवेश करे।

(2) इकाई को अपना वाणिज्यिक उत्पादन 31 मार्च, 2030 से पहले प्रारंभ करना आवश्यक होगा।

(3) कुल पूंजी निवेश एवं रोजगार गणना की समय-सीमा-

(i) उद्यम आकांक्षा दिनांक अथवा भूमि / भवन आबंटन दिनांक अथवा भू-आधिपत्य दिनांक, जो पूर्ववर्ती हो, से प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक एवं उसके अगले 5 वर्षों तक किए गए स्थायी पूंजी निवेश को कुल निवेश में शामिल किया जाएगा।

(ii) प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ दिनांक से 5 वर्षों तक उत्पन्न रोजगार को भी कुल रोजगार में सम्मिलित किया जाएगा।

(iii) इकाई को इस पैकेज का लाभ तभी प्राप्त होगा, जब वे वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने से 5 वर्षों के भीतर न्यूनतम 1000 करोड़ का निवेश करेगा। तब तक इकाई औद्योगिक विकास नीति के अध्याय (स-4) में उल्लेखित पैकेज हेतु पात्र होगी।

(iv) न्यूनतम 1000 करोड़ का निवेश अथवा न्यूनतम 1000 रोजगार प्रदान करने पर इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ दिनांक से इस पैकेज के अंतर्गत उल्लेखित अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन एरियर्स के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

(4) इकाई को औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका (12.19) में उल्लेखित शर्तानुसार छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को रोजगार प्रदान करना होगा।

4. इस पैकेज में उल्लिखित शब्दों का अर्थान्वयन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 एवं इसके क्रियान्वयन के लिए बने नियमों के अनुसार होगा। इस पैकेज का क्रियान्वयन सम्बंधित छूट, अनुदान, प्रतिपूर्ति हेतु जारी नियमों में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, तथा आवश्यक दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी किए जा सकेंगे।

यह अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रजत कुमार, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29 सितम्बर 2025

अधिसूचना

क्र. GENCOR-35/2648/2025-C&I.— राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य में औद्योगिक विकास को अधिक गति प्रदान करने के लिए लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव, राज्य शासन, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका (12.29) एवं अध्याय (स-6) की कंडिका (13) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसरण में, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के माध्यम से राज्य में वृहद उद्योग की स्थापना हेतु, राज्य में “आई.टी.” सेक्टर में निवेश हेतु, मेसर्स वीराइज प्रायवेट लिमिटेड के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज (बी-स्पोक पैकेज) का निर्धारण निम्नानुसार करता है:-

1. औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए “आई.टी. सेक्टर” के लिए अध्याय (स-6) में प्रावधान किए गए हैं। मेसर्स वीराइज प्रायवेट लिमिटेड द्वारा राज्य में डेटा साइंस, डिजिटल इंजीनियरिंग एवं आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस सेवा हेतु 86 करोड़ रुपये निवेश एवं 1300 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजित होना प्रस्तावित किया गया है।

2. इस पैकेज के अंतर्गत निम्नानुसार अनुदान/छूट/रियायत की मदवार स्वीकृति की जाती है:-

(1) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान - मान्य स्थायी पूंजी निवेश का 50%, 6 वार्षिक किश्तों में वितरित। प्रथम किश्त स्वीकृत अनुदान राशि के 1/6 होगी, अन्य किश्तें वित्तीय वर्ष के टर्नओवर का 10% अथवा स्वीकृत अनुदान राशि के 1/6, जो न्यूनतम हो, होगी।

(2) रोजगार सृजन प्रोत्साहन - 5 वर्षों की अवधि तक वेतन का अधिकतम 20% तक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिसमें प्रति कर्मचारी अधिकतम रु. 1,00,000 तक की सैलरी की सीमा होगी। यह प्रोत्साहन केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी कर्मचारियों को मिलेगा, जिनका ईपीएफओ (EPFO) पंजीकरण मे इकाई में नियोजन से अधिकतम 3 वर्ष पूर्व का हो एवं जिन्हें इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के 5 वर्षों के भीतर भर्ती किया गया है।

(3) ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति - छत्तीसगढ़ निवासी कर्मचारियों के लिए 5 वर्षों तक पीएफ अंशदान का 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसमें प्रति कर्मचारी अधिकतम रु. 3000 प्रति माह की सीमा होगी। यह प्रोत्साहन केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी कर्मचारियों को मिलेगा, जिनका ईपीएफओ (EPFO) पंजीकरण मे इकाई में नियोजन से अधिकतम 3 वर्ष पूर्व का हो एवं जिन्हें इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के 5 वर्षों के भीतर भर्ती किया गया है।

(4) अन्य अनुदान/ प्रतिपूर्ति - उपरोक्त वर्णित निवेश प्रोत्साहनों के अतिरिक्त इकाई को औद्योगिक विकास नीति के अध्याय स-6 के बिन्दु क्र (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (11) एवं (12) में उल्लेखित निवेश प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

3. यह पैकेज निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा-

(1) आर्थिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता - कंपनी को इस पैकेज का लाभ तभी मिलेगा जब वह न्यूनतम रु. 1000 करोड़ का स्थायी पूंजी निवेश करे अथवा 1000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करे।

(2) इकाई को अपना वाणिज्यिक उत्पादन 31 मार्च, 2030 से पहले प्रारंभ करना आवश्यक होगा।

(3) कुल पूंजी निवेश एवं रोजगार गणना की समय-सीमा-

(i) उद्यम आकांक्षा दिनांक अथवा भूमि / भवन आबंटन दिनांक अथवा भू-आधिपत्य दिनांक, जो पूर्ववर्ती हो, से प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक एवं उसके अगले 5 वर्षों तक किए गए स्थायी पूंजी निवेश को कुल निवेश में शामिल किया जाएगा।

(ii) प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ दिनांक से 5 वर्षों तक उत्पन्न रोजगार को भी कुल रोजगार में सम्मिलित किया जाएगा।

(iii) इकाई को इस पैकेज का लाभ तभी प्राप्त होगा जब वे वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने से 5 वर्षों के भीतर न्यूनतम 1000 युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा। तब तक इकाई औद्योगिक विकास नीति के अध्याय स-6 में उल्लेखित पैकेज हेतु पात्र होगी।

(iv) 1000 रोजगार प्रदान करने पर इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ दिनांक से इस पैकेज के अंतर्गत उल्लेखित अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन एरियर्स के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

(4) इकाई को औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका (12.19) में उल्लेखित शर्तानुसार छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को रोजगार प्रदान करना होगा।

4. इस पैकेज में उल्लिखित शब्दों का अर्थान्वयन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 एवं इसके क्रियान्वयन के लिए बने नियमों के अनुसार होगा। इस पैकेज का क्रियान्वयन सम्बंधित छूट, अनुदान, प्रतिपूर्ति हेतु जारी नियमों में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, तथा आवश्यक दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी किए जा सकेंगे।

यह अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रजत कुमार, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29 सितम्बर 2025

अधिसूचना

क्र. GENCOR-35/2648/2025-C&I. — राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य में औद्योगिक विकास को अधिक गति प्रदान करने के लिए लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव, राज्य शासन, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका (12.29) एवं अध्याय (स-7) की कंडिका (13) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसरण में, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के माध्यम से राज्य में वृहद उद्योग की स्थापना हेतु, राज्य में “आईटी इनेबल्ड सर्विसेस (आई.टी.ई.एस.)” सेक्टर में निवेश हेतु, मेसर्स स्कवेयर बिजनस सर्विसेज प्राय. लिमि. एवं मेसर्स टेलीपरफॉर्मेंस ग्लोबल बिजनस प्राय. लिमि. के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज (बी-स्पोक पैकेज) का निर्धारण निम्नानुसार करता है:-

1. औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए "आई.टी.ई.एस. सेक्टर" के लिए अध्याय (स-7) में प्रावधान किए गए हैं। मेसर्स स्कवेयर बिजनस सर्विसेज प्राय. लिमि. एवं मेसर्स टेलीपरफॉर्मेंस ग्लोबल बिजनस प्राय. लिमि. द्वारा राज्य में बिजनस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) सेवा हेतु क्रमशः 07 करोड़ एवं 6.5 करोड़ रुपये निवेश एवं 1400 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजित होना प्रस्तावित किया गया है।

2. इस पैकेज के अंतर्गत निम्नानुसार अनुदान/छूट की मदवार स्वीकृति की जाती है:-

(1) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान - मान्य स्थायी पूंजी निवेश का 50%, 6 वार्षिक किश्तों में वितरित किया जाएगा। प्रथम किश्त स्वीकृत अनुदान राशि के 1/6 होगी, अन्य किश्तें वित्तीय वर्ष के टर्नओवर का 10% अथवा स्वीकृत अनुदान राशि के 1/6, जो न्यूनतम हो, होगी।

(2) MPLS/ILL व्यय प्रतिपूर्ति (मेसर्स टेलीपरफॉर्मेंस ग्लोबल बिजनस प्रा.लि हेतु) - Multi-Protocol Label Switching / Internet Lease Line की स्थापना पर व्यय का 100%, अधिकतम रु. 1.7 करोड़ की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(3) रोजगार सृजन प्रोत्साहन - रु 50,000 तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के मूल निवासी कर्मचारियों के लिए 5 वर्षों की अवधि तक वेतन का अधिकतम 20% तक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

(4) ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति - छत्तीसगढ़ के मूल निवासी कर्मचारियों के लिए 5 वर्षों तक नियोक्ता के पीएफ अंशदान का 75% प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(5) विद्युत शुल्क छूट - वाणिज्यिक सेवा गतिविधि प्रारंभ दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट प्रदान किया जाएगा।

(6) ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी अनुदान को छोड़कर औद्योगिक विकास नीति के परिशिष्ट-7 में उल्लेखित अन्य निवेश प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

3. यह पैकेज निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा-

(1) आर्थिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता - कंपनी को इस पैकेज का लाभ तभी मिलेगा जब

वह न्यूनतम 1000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करे।

(2) इकाई को अपना वाणिज्यिक उत्पादन 31 मार्च, 2030 से पहले प्रारंभ करना आवश्यक होगा।

(3) कुल पूंजी निवेश एवं रोजगार गणना की समय-सीमा-

(i) उद्यम आकांक्षा दिनांक अथवा भूमि/भवन आबंटन दिनांक अथवा भू आधिपत्य दिनांक जो पूर्ववर्ती हो से प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक एवं उसके अगले 2 वर्षों तक किए गए स्थायी पूंजी निवेश को कुल निवेश में सम्मिलित किया जाएगा।

(ii) प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ दिनांक से 5 वर्षों तक उत्पन्न रोजगार को भी कुल रोजगार में सम्मिलित किया जाएगा।

(iii) इकाई को इस पैकेज का लाभ तभी प्राप्त होगा जब वे वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने से 5 वर्षों के भीतर न्यूनतम 1000 युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा। तब तक इकाई औद्योगिक विकास नीति के परिशिष्ट-7 में एमएसएमई सेवा उद्यम हेतु उल्लेखित पैकेज हेतु पात्र होगी।

(iv) न्यूनतम 1000 रोजगार प्रदान करने पर इकाई को वाणिज्यिक सेवा गतिविधि प्रारंभ दिनांक से इस पैकेज के अंतर्गत उल्लेखित अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन एरियर्स के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

(4) इकाई को औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका (12.19) में उल्लेखित शर्तानुसार छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को रोजगार प्रदान करना होगा।

4. इस पैकेज में उल्लिखित शब्दों का अर्थान्वयन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 एवं इसके क्रियान्वयन के लिए बने नियमों के अनुसार होगा। इस पैकेज का क्रियान्वयन सम्बंधित छूट, अनुदान, प्रतिपूर्ति हेतु जारी नियमों में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, तथा आवश्यक दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी किए जा सकेंगे।

यह अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.